REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 9 | JUNE - 2019

जनता पार्टी के शासन काल में : भारत , सोवियत एवं अमेरिका के सम्बन्ध

मन्दाकिनी राय
शोध छात्रा, पाश्चात्य इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय , लखनऊ.

प्रस्तावना :–

'भारतीय राजनीति में सन् 1977 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। यह देश सन् 1975 से लेकर सन् 1977 तक विकट परिस्थितियों से गुजरा, जिसके प्रभाव से समाज का कोई वर्ग अछूता नही रहा। जे0 पी0 आन्दोलन से लेकर आपातकाल की परिस्थितियों ने भारतीय राजनीति के आन्तरिक एवं बाह्य दोनो , देश की छवि पर गलत प्रभाव डाल रहे थे। सन् 1976 में होने वाले चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया। सरकार के इस निणर्य को देश के बुद्धजीवी वर्ग, डॉक्टर, वकील, पत्रकार इत्यादि ने देश के लोकतंत्र को खतरे के रूप में देखा और इसकी भर्त्सना की। ' 18 जनवरी 1977 को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने आकस्मिक घोषणा की लोकसभा चुनाव मार्च में कराये जायेंगे। इसी घोषणा के साथ राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया, प्रेस सेंसरशिप, सार्वजनिक सभाये करना और राजनीतिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। सभी राजनीतिक दलों को पूरी स्वतंत्रता दी गयी की वह खुलकर प्रचार–प्रसार करें।

लोकसभा का चुनाव 16 मार्च को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न हुआ। इस चुनाव में कॉंग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी भी चुनाव हार गये। श्रीमती गांधी ने जनता के इस निर्णय को उचित बताते हुए विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया '।[1]

जे0 पी0 आन्दोलन के परिणामस्वरूप जनता पार्टी शासन में आयी। इंदिरा के जाने के बाद मार्च सन् 1977 जनता पार्टी का शासन आया जिसमें मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनें। पहली बार भारत में गैर कॉंग्रेसी सरकार का गठन हुआ। कहने को तो गैर कॉंग्रेसी सरकार थी परन्तु इसके बहुत से ऐसे सदस्य थे जो आजीवन कॉंग्रेसी थे या गांधीवादी थे। इस सरकार में सभी प्रकार की विचारधाराओं का मिश्रण था। कॉंग्रेस आर , जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, आर0 एस0, एस0 देश की अन्य क्षेत्रीय दल इसमे समाहित हुए। मोरारजी देसाई भी पहले कॉंग्रेस में ही थे। पार्टी के विभाजन के बाद सिंडीकेट समूह में आ गए थे। वेल्स हैंगन के अनुसार – '' मोरारजी देसाई ऐसे राजनेताओं में से थे जो कि किसी के लिए भी प्रतिबद्ध नहीं थे। वह किसी विचारधारा के लिए भी प्रतिबद्ध नहीं थे। वेल्स हैंगन हमेशा उन्हें एक प्रशासक मानते थे। कुशलता और वैद्यता उनके काम करने के मानक थे ''।[2]

[1] चन्द विपन्न , आजादी के बाद भारत

[2]हैंगन वेल्स, ऑफ्टर नेहरू , हू ? पेज न0 31, रूपर्ट हार्ट– डेविस , लंदन 1963, प्रिन्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1963, सॉल डिस्ट्रीब्यूटेड इन इन्डिया यूनीवर्सल बुक , कानपुर यू0 पी0.

जनता पार्टी और भारतीय विदेशनीति – सोवियत और अमेरिका की भूमिका–' भारत में मोराजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद विभिन्न प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे, कि भारत की विदेश नीति में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। यह उम्मीद की जा रही थी कि सोवियत यूनियन को जनता पार्टी की सरकार के साथ सामंजस्य बनाना कठिन होगा। सामान्यतः यह माना जा रहा था कि जनता पार्टी के नए मंत्री , जो आपातकाल के समय जेल में बंद थे, जिसके कारण वह सोवियत यूनियन के प्रति द्वेषपूर्ण भाव रखेंगे। नए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और उनके विदेश मामलों के मंत्री अटल बिहारी बाजपेई ने यह आश्वासन दिया कि भारत की गुटनिरपेक्षता वास्तविक होगी। मोरारजी देसाई ने कहा कि – उनकी सरकार *'उचित' और 'वास्तविक'* गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाएगी जो कि किसी भी प्रकार के गुट बनाने के सन्देह से मुक्त हो । भले ही देसाई जी ने अपने वक्तव्य में सोवियत यूनियन का जिक्र नही किया परन्तु यह स्पष्ट था कि उनका आक्रमण सोवियत यूनियन द्वारा जनता पार्टी के नेतृत्व की आलोचनाओं के खिलाफ था '।[3]

'अफगानिस्तान के सामरिक तथा राजनैतिक महत्व ने ' गृह–युद्ध 'में बाहरी हस्तक्षेप को अनिवार्य बना दिया था। यह हस्तक्षेप , मुख्यतः पाकिस्तान द्वारा दक्षिण एशिया में शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा था। मोरारजी देसाई की सोवियत यूनियन की यात्रा के बाद जो संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ था वह अफगानिस्तान की दशा को महत्व दे रहा था। अफगान लोगों की स्वतंत्रता रक्षा तथा काबुल के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने की इच्छा को अभिव्यक्ति भारत की पारंपरिक नीति के अनुरूप थी '।[4]

' सन् 1979 जून में छपी खबर के अनुसार मास्को में हुए भारत–सोवियत सम्मेलन इस बात पर सहमति के साथ समाप्त हुआ कि अफगानिस्तान के आन्तरिक मामलें में किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान देसाई एवं रूसी प्रधानमंत्री कोसीजिन ने इस बात का संकेत दिया और अंत में देसाई एवं ब्रेजनेव के मध्य विस्तारपूर्वक बात हुई। क्रेमलिन में 90 मिनट की बातचीत के बाद श्रीमान देसाई एवं ब्रेजनेव ने एक संयुक्त घोषणा की जिसमें दोनों नेताओं के मतों को अफगानिस्तान एवं दक्षिणपूर्वी एशियाई क्षेत्रों को समाविष्ट किया गया'। कोसीजिन ने यह आरोप लगाया कि अफगानिस्तान में हो रही विध्वंशक गतिविधियों के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है'।[5]देसाई ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे है परन्तु भारत ही एक ऐसा है जो इस बात पर ध्यान दे रहा था कि अफगानिस्तान में कोई समस्या ना उत्पन्न हो और भी देश अन्य देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। देसाई ने कहा कि सोवियत यूनियन तथा भारत का उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता कायम रखना है, जहां पर नये विवाद उत्पन्न हो गये है वहां स्थिरता बनाये रखने के लिए एक ही रास्ता है कि बाह्य हस्तक्षेप को तुरन्त रोका जाये '।[6]

' प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जून में हुई , यू0 एस0 के अधिकारिक यात्रा के कुछ सप्ताह पूर्व ही कुछ क्षेत्रों में यह धारणा व्यक्त की जा रही थी कि सोवियत–अमेरिकी सम्बन्धों में आयी भारी गिरावट भारत–अमेरिकी सम्बन्धों को भी प्रभावित करेगी। उस समय के सभी स्तम्भकार एवं टीकाकारों का मनना था कि इतने सालों में अमेरिका–सोवियत के सम्बन्ध अत्यन्त ही खराब रहे और अपनी संदिग्ध स्थिति में है और कुछ तो मास्को को इस बदनियत के लिए अपराधी ठहरा रहे थे। इस दौरान कार्टर प्रशासन ने दुनिया भर में सोवियत की आलोचना करना तथा उसे चेतावनी देना प्रारम्भ कर दिया था। इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए स्तम्भकार कार्ल टी0 रॉवन ने कहा कि – '' यह शत्रुतापूर्ण भिड़ंत सोवियत अमेरिकन युद्ध के लिए कम पड़ जायेगी जिसकी भविष्यवाणी पिकिंग के नेता कर रहे है , परन्तु एक और लम्बा और कठोर समय है , जो अपरिहार्य लगता है ''।[7]

' कार्टर प्रशासन द्वारा सोवियत नीति पर आक्रमण ने कूटनितिज्ञों को डरा दिया है और अब यह धारणा थी कि, जैसा कि डलेस के काल में था , यू0 एस0 अब तीसरी दुनिया के उन देशों की गणना शुरू कर रहा

[3]गयकवाड़ संजय, डॉयनामिक्स ऑफ इण्डो–सोवियत रिलेशन – द एरा ऑफ इंदिरा गांधी, पमज न0 135, दीप एण्ड दीप पब्लकेशनस।

[4]द ट्रिब्यून , 19 जून 1979 , जनता पार्टी पेर्पस , प्रेस क्लिपिंग 4 , पेज न0 10 तीन मूर्ति अभिलेखागार , नई दिल्ली.

[5]टाइम्स ऑफ इंडिया , 19 जून 1979, जनता पार्टी पेर्पस , प्रेस क्लिपिंग 4 , पेज न0 43 तीन मूर्ति अभिलेखागार , नई दिल्ली.

[6]वही , 19 जून 1979, जनता पार्टी पेर्पस , प्रेस क्लिपिंग 4 , पेज न0 43 तीन मूर्ति अभिलेखागार , नई दिल्ली.

[7]वी. एम. कामथ , यु0 एस0 डिस्कस सोवियत रोल इन अफ्रीका वीद देसाई , टाइम्स ऑफ इंडिया 6 जून 1978 जनता पार्टी पेपर्स प्रेस क्लिपिंग 4, पेज न0 192 , तीन मूर्ति संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली।

था जो उसके साथ है। यह धारणा थी कि अफ्रीका, अपरिहार्य रूप से , कार्टर–देसाई एजेण्डे के साथ खड़ा रहेगा और भारत को अमेरिकी नजरिए से, तथाकथित अफ्रीका में सोवियत द्वारा हस्तक्षेप दिखाने के प्रयास किए जाएंगे। हाल ही में अमेरिकन टेलीविजन टीम के साथ दिए साक्षात्कार के दौरान देसाई जी ने कहा कि – '' हमकिसी के तरफ अधिक झुकाव नही रखेंगे ''। इस साक्षात्कार में कुछ मुद्दों पर देसाई जी अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर खो दिया। चूंकि यह सवाल प्राथमिकता प्राप्त कर रहा है, इसलिए भारत को यह निश्चित करना होगा कि वह अफ्रीका में किस प्रकार महाशक्तियों से आमना – सामना करेगा और स्थिति को सम्भाल पायेगा। किसी भी प्रकार से यह स्पष्ट नहीं था कि वाशिंगटन के दिमाग में क्या चल रहा है जैसा कि वाशिंगटन पोस्ट के मुरे मार्डर ने कल कहा कि– जिस दुविधा से, वाशिंगटन तथा मॉस्को , दोनो ही सम्मुख हो रहे थे वह विचित्र थी क्योंकि दोनो ही पक्षों के कूटनितिज्ञ सहमत थे कि घटनाओं ने दोनो ही देशों को असाधारण स्थिति में पहुंचा दिया है और इस दुविधा का असम्पूर्ण अंश ही जनचेतना तक पहुंचा है। कुछ लोगों को यह भरोसा था कि भारत अभी भी संयमित भूमिका निभा सकता है और इसी कारण से प्रधानमंत्री जी की यात्रा में विशेष दिलचस्पी दिखाई जा रही थी '।[8]

' भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपनी अमेरिकी यात्रा की जिसमें उन्होंने नेशनल टेलीकास्ट कार्यक्रम के दौरान यह साफ कर दिया कि, भारत का परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का सवाल ही नहीं उठता, जब तक कि बड़ी शक्तियां हमे परमाणु विस्फोटक बनाने और उसका परीक्षण करने नहीं देती। इस विषय पर भारत का मतभेद साफ जाहिर होता है। देसाई ने चार अमेरिकी पत्रकारों के पैनल को अपना साक्षात्कार दिया था। उसको अमेरिका की नेशनल ब्राडकास्टिंग कम्पनी ने यह दोहराया कि भारत ने यह निर्णय लिया है कि ना वह न्यूक्लियर बनाएगा ना ही विस्फोट करेगा, यहां तक कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि – '' यह संधि भेदभावपूर्ण है और हमारे आत्मसम्मान के विरूद्ध है ''।[9] इस बातचीत ने यह दर्शा दिया कि भारत की स्थिति को अमेंरिका ने नही समझा इस बात को प्रधनमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया और यह आशा व्यक्त की कि आगे समझेगा। देसाई जी से इस बिन्दु पर भी पूछा गया कि – क्या तारापुर से होने वाले आपूर्ति के मुद्दे को लेकर भारत एवं यू0 एस0 के बीच टकराव बढ़ रहा था या यह सवाल सुलझ जायेगा ?। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के सवाल किये गये , जिसमें एक प्रश्न ये भी था कि – भारत अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए परमाणु स्थापना की अनुमति देने के लिए तैयार क्यों नही था ?। इसके जबाब में देसाई जी ने कहा कि – ''क्या आप यू0 एस0 के कांग्रेस को सभी परमाणु प्रतिष्ठानों को निरीक्षण के लिए खोलेगें '' ?। '' यह पारस्परिक होना चाहिए। क्योंकि आप शक्तिशाली है , आप हमें नीचे नही ला सकते। जब आप कहते है कि हम परमाणु हथियारों का उत्पादन नही कर रहे है, तो आपको विशेष रूप से दूसरों के लिए अधिक विचार करना चाहिए ''।[10] इस प्रकार से भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के सन्दर्भ में अपने पक्ष को रखा, और यह बताया कि क्यों भारत इस पर हस्ताक्षर नही कर रहा है।

' इस यात्रा में भारत और अमेरिकी नीति में पहले की अपेक्षा कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, देसाई जी और कार्टर के बीच बातचीत में मधुरता दिखती है और वही इसके पहले बांगलादेश के युद्ध से पूर्व निक्सन और इंदिरा जी के बीच हुई ऐतिहासिक बैठक में विरोधाभाष दिखता है। भारत–सोवियत सम्बन्धों के साकारात्मक पक्षों पर ज्यादा और बांटने वाले मुद्दों पर कम जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने संबंध को बेहतर करने के लिए रचनात्मक कार्य करने के बारे में सोचा। यदि इंदिरा और निक्सन किसी विशेष परिस्थितियों के शिकार थे तो कार्टर और देसाई अलग तथा खुशहाल परिस्थितियों के लाभार्थी थे, जिसने उन्हें एक दूसरे के प्रति सभ्य तथा आदरपूर्वक बात करने के लिए अनुमति दी। भारतीय व्यापारी यह जानकर प्रसन्न होंगे की यू0 एस0 सरकार '

[8]वी. एम. कामथ , यु0 एस0 डिस्कस सोवियत रोल इन अफ्रीका वीद देसाई , टाइम्स ऑफ इंडिया 6 जून 1978 जनता पार्टी पेपर्स प्रेस क्लिपिंग 4, पेज न0 192 , तीन मूर्ति संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली।

[9]टाइम्स ऑफ इंडिया , 12 जून 1978 , जनता पार्टी पेपर्स प्रेस क्लिपिंग 4, पेज न0 178 , तीन मूर्ति संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली।

[10], वही , 12 जून 1978 , जनता पार्टी पेपर्स प्रेस क्लिपिंग 4, पेज न0 178 , तीन मूर्ति संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली।

अमेरिकी व्यापारिक कार्यकारिणी 'की नियुक्ति को स्वीकार करेगी जो कि दिल्ली में यू0 एस0 तथा भारतीय कार्पोरेशन, जो तीसरे देश उद्यम में रूचि रखते है , उनके मध्य ' मैच मेकर ' के जैसे काम करेगा '।[11]

उपसंहार

भारत की विदेश नीति में जनता पार्टी के शासन काल में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके पूर्व भारत के प्रति रूस और अमेरिका के नीतियों में बड़ा अन्तर दिखता है। भारत के साथ जहां अन्तराष्ट्रीय मंच पर रूस सभी प्रश्नों पर साथ खड़ा है वही अमेरिका का रूख नाकारात्मक रहा। निक्सन प्रशासन से लेकर फोर्ड तक , भारत की आवश्यकताओं पर अमेरिका का रूख भारत के विरूद्ध ही रहा ,चाहे बांगलादेश का मामला हो, कश्मीर का मुद्दाहोया भारत में खाद्यान की समस्या। जनता पार्टी और कार्टर प्रशासन की नीतियों में थोड़ी साकरात्मकता आयी। चूंकि भारत गुटनिरपेक्ष नीति का पालन कर रहा था और ऐसी स्थिति में रूस का भारत के साथ खड़ा रहना दुनिया के अन्य देशों के लिए शंका का विषय था। भारत पर लग रहे आरोप , कि वह गुटनिरपेक्ष स्वयं को मानता है पर है नही। उस भारत अपने को इस छवि से निकालना चाह रहा था , लेकिन अमेरिका भी महाशक्ति था तो उसके लिए भारत महत्वपूर्ण था।अमेरिका सभी प्रकार के दबाव बना रहा था कि भारत उसके पक्ष में आ जाए। चूंकि भारत के लिए एसी परिथतियो में किसी एक पक्ष के साथ जाना संभव नही था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 गयकवाड़ संजय, डॉयनामिक्स ऑफ इण्डो–सोवियत रिलेशन – द एरा ऑफ इंदिरा गांधी, , दीप एण्ड दीप पब्लकेशनस।

2 चन्द विपन्न , आजादी के बाद भारत टाइम्स ऑफ इंडिया , 19 जून 1979, जनता पार्टी पेर्पस , प्रेस क्लिपिंग 4 , पेज न0 43 तीन मूर्ति अभिलेखागार , नई दिल्ली.

4द ट्रिब्यून , 19 जून 1979 , जनता पार्टी पेर्पस , प्रेस क्लिपिंग 4 , पेज न0 10 तीन मूर्ति अभिलेखागार , नई दिल्ली.

5वी. एम. कामथ , यु0 एस0 डिस्कस सोवियत रोल इन अफ्रीका वीद देसाई , टाइम्स ऑफ इंडिया 6 जून 1978 जनता पार्टी पेपर्स प्रेस क्लिपिंग 4, पेज न0 192 , तीन मूर्ति संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली।

6 हैंगन वेल्स, ऑफ्टर नेहरू , हू ? रूपर्ट हार्ट– डेविस , लंदन 1963, प्रिन्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1963, सॉल डिस्ट्रीब्यूटेड इन इन्डिया यूनीवर्सल बुक , कानपुर यू0 पी0.

मन्दाकिनी राय
शोध छात्रा, पाश्चात्य इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय , लखनऊ.

[11]टाइम्स ऑफ इन्डिया , 15 जून 1978 , जनता पार्टी पेपर्स प्रेस क्लिपिंग 4, पेज न0 178 ,नेहरू स्मारक ,संग्रहालय एवं पुस्तकालय , पाण्डु लिपी विभाग ,नई दिल्ली।